

जी.सी.मितल और एस.एस.सोढ़ी जे.जे. के समक्ष।

आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक, -याचिकाकर्ता।

बनाम

एम/एस प्रिसिजन स्टील एंड इंजीनियरिंग। वर्क्स, फ़रीदाबाद। - प्रतिवादी।

1986 का आयकर संदर्भ संख्या 4

4 मई 1989.

आयकर ☒ धिनियम (1961 का XLIII) - धारा 40 (बी), स्पष्टीकरण (1) - फर्म के साथ जमा करने वाले भागीदार - ऐसी जमा पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं - भागीदार फर्म से निकासी पर ब्याज भी दे रहे हैं - प्राप्त ब्याज से ☒ अधिक ब्याज का भुगतान किया जाता है - निर्धारित फर्म की आय में भुगतान किए गए ब्याज पर ☒ तिरिक्त छूट - ऐसे ☒ तिरिक्त की वैधता - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र - ऐसे परिपत्र का मूल्य।

यह माना गया कि केवल फर्म द्वारा ☒ पने साझेदारों को भुगतान की गई शुद्ध राशि, साझेदारों द्वारा फर्म को भुगतान किए गए ब्याज को समायोजित करने के बाद, आयकर ☒ धिनियम, 1961 की धारा 40 (बी) के तहत ☒ स्वीकार्य हो सकती है चूँकि इस मामले में साझेदारों ने फर्म को ☒ अधिक ब्याज का भुगतान किया था, इसलिए फर्म द्वारा साझेदारों को दिए गए ब्याज

को ट्रिब्यूनल द्वारा ❑ स्वीकार नहीं किया गया था और ❑ तिरिक्त राशि को हटाने में ट्रिब्यूनल सही था।

माना गया कि बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र ❑ दालतों पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि यदि निर्धारिती इसकी शुद्धता को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए खुला है। लेकिन साथ ही, बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी है और विभाग को बोर्ड के निर्णय के विरोध में तर्क देने की ❑ नुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में, हमें परिपत्र को प्रभावी बनाना होगा, क्योंकि यह करदाता के पक्ष में है और विभाग को बाध्य करेगा।

(पैरा 4)

आयकर ❑ धिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर ❑ पीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली बेंच) नई दिल्ली द्वारा, उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर राय के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को संदर्भ ट्रिब्यूनल का आदेश दिनांक 26 मार्च 1984 आर.ए. नंबर 768/डेल/84 आईटीए नंबर, 1867/डेल/83, आकलन वर्ष 1981-82:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण आयकर ❑ धिनियम, 1961 की धारा 40 (बी) के तहत भागीदारों को भुगतान किए गए ब्याज के रूप में 1,08,287 रुपये की ❑ तिरिक्त राशि को हटाने में कानूनन सही था"?

आवेदक की ओर से वरिष्ठ ❑ धिवक्ता ❑ शोक भान और ❑ धिवक्ता ❑ जय मित्तल।

प्रतिवादी की ओर से ✕ मिता गुप्ता, ✕ धिवक्ता।

निर्णय

गोकल चंद मितल, जे

(1)निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म है। निर्धारण वर्ष 1981-82 से संबंधित वर्ष के दौरान, चालू खाते में उनके द्वारा की गई निकासी पर भागीदारों से 1,62,41Q रुपये का ब्याज मिला। साझेदारों ने फर्म में जमा किए थे और उस ✕ वधि के दौरान उन जमाओं पर उन्हें 1,08,287 रुपये का ब्याज दिया गया था। मूल्यांकन के दौरान, आयकर ✕ धिकारी ने आयकर ✕ धिनियम, 1961 (इसके बाद '✕ धिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 40 (बी) के तहत 1,08,287 रुपये का ब्याज वापस जोड़ा, भागीदारों को भुगतान किए गए ब्याज की कटौती की ✕ नुमति नहीं दी जा सकी। निर्धारिती को आयकर आयुक्त (✕ पील) से कुछ राहत मिली। आयकर ✕ पीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण'), दिल्ली में आगे ✕ पील करने पर, निर्धारिती को भागीदारों को भुगतान किए गए 1,08,287 रुपये के ब्याज के संबंध में पूरी राहत मिली। आदेश में उल्लिखित कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए। इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय की राय के लिए भेजा गया है: "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल आयकर ✕ धिनियम, 1961 की धारा 40 (बी) के तहत भागीदारों को भुगतान किए गए ब्याज के रूप में 1,08,287 रुपये की ✕ तिरिक्त कटौती करने में कानूनन सही था?"

(2) आईटी ङ धिनियम की धारा 40 (बी) कहती है कि मूल्यांकन वर्ष के दौरान प्रश्न इस प्रकार थे:

“40. धारा 30 से 39 में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, 'व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना में निम्नलिखित राशियाँ नहीं काटी जाएंगी:

9(ए) xxxxxxxxxxxzxxx

(बी) किसी भी फर्म के मामले में, फर्म द्वारा फर्म के किसी भी भागीदार को किया गया ब्याज, वेतन, बोनस कमीशन या पारिश्रमिक का कोई भी भुगतान।

उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित मामलों में चार उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया और इसी तरह के तथ्यों पर यह माना गया कि केवल फर्म द्वारा ङ पने भागीदारों को भुगतान की गई शुद्ध राशि, भागीदारों द्वारा फर्म को भुगतान किए गए ब्याज को समायोजित करने के बाद, ङ धिनियम की धारा 40(बी) के तहत इसकी ङ नुमति नहीं दी जा सकती है, न कि संपूर्ण रूप से।

(i) सी.आई.टी. बनाम कैलाश मोटर¹

(ii) सी.आई.टी. बनाम टी. वी. रामनैय्या एंड संस²

(iii) सी.आई.टी. बनाम कोठारी एंड कंपनी³

¹ (1) 134 आई.टी.आर. 312 (सभी)।

² (2) 157 आई.टी.आर. 300 (एपी)

³ (3) 165 आई.टी.आर. 594 (कर्नाटक)

(iv) सी.आई.टी. बनाम मोती लार्ड रामजीवन एंड कंपनी

हालाँकि, **सी.आई.टी. तमिलनाडु बनाम ओ.एम.एस.एस. शंकरलिंगा नादर एंड कंपनी** में

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण पनाया गया है।

(3) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1894 द्वारा, अधिनियम की धारा 40 (बी) में तीन प्रावधान शामिल किए गए, जो 1 अप्रैल, 1985 से लागू हुए और स्पष्टीकरण (1) जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। निम्नलिखित नुसार :

"स्पष्टीकरण 1: जहां किसी फर्म द्वारा फर्म के किसी भागीदार को ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिसने फर्म को ब्याज का भुगतान भी किया है, इस खंड के तहत स्वीकृत की जाने वाली ब्याज की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिसके द्वारा फर्म द्वारा साझेदार को ब्याज का भुगतान साझेदार द्वारा फर्म को ब्याज के भुगतान से अधिक हो जाता है।

यह स्पष्टीकरण निर्धारिती की ओर से संदर्भित चार उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप है। स्पष्टीकरण सम्मिलित करने के बाद, केंद्रीय कर निदेशक बोर्ड के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या स्पष्टीकरण भावी रूप से लागू होगा या केवल स्पष्टीकरण प्रकृति का होगा और उन मामलों में पहले के वर्षों के लिए भी लागू होगा जो न्यायालयों में लंबित हो सकते हैं। केंद्रीय

⁴ (4) 171 आई.टी.आर. 294 (राजस्थान)

⁵ (5) 147 आई.टी.आर. 332.

प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाता के पक्ष में फैसला लिया, जो 149 आई.टी.आर. में छपा है। (क्रानून 127). बोर्ड के निर्णय का प्रासंगिक पैरा, जो इस मामले के निर्णय से संबंधित हो सकता है, इस प्रकार है: -

“(2) विधायी मंशा को अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं ताकि इन प्रावधानों के वास्तविक इरादे और उद्देश्य के बारे में आगे विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सके। उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए :

(ए) यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां कोई फर्म किसी भागीदार को ब्याज का भुगतान करती है और साथ ही उससे ब्याज भी प्राप्त करती है,

केवल फर्म द्वारा साझेदार को भुगतान की गई शुद्ध राशि को फर्म की आय की गणना में आयकर अधिनियम की धारा 40 (बी) के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण (1) जो 1 अप्रैल 1985 से लागू हुआ, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और भागीदारों को भुगतान की गई शुद्ध राशि, यदि कोई हो, को स्वीकार किया जा सकता है।

लेकिन यदि परिणाम यह हुआ कि साझेदारों द्वारा फर्म को भुगतान की गई राशि फर्म द्वारा साझेदारों को भुगतान की गई राशि से अधिक थी, तो फर्म द्वारा साझेदारों को भुगतान की गई

ब्याज की राशि को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। जब यह प्रावधान 1 अप्रैल, 1985 से इतना स्पष्ट था, तो केंद्रीय बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने का कोई सवाल ही नहीं था, जब

तक कि यह नहीं माना जाता कि स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण प्रकृति का था और स्पष्टीकरण (1)

लागू होने से पहले भी मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा। उपरोक्त निर्णयों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि बोर्ड का निर्णय स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और संशोधन 1 ४ प्रैल, 1985 से पहले के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा। हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने ओ.एम.एस.एस. शंकरलिंगा नादर एंड कंपनी के मामले (सुप्रा) ने एक ४ लग दृष्टिकोण ४ पनाया। इस मामले पर हमने आई.टी. संदर्भ। 1981 की संख्या 43 (हिंदुस्तान स्टील फोर्जिंग राजपुरा बनाम सी.आई.टी. पटियाला (6), कि बोर्ड का उपरोक्त निर्णय स्पष्ट प्रकृति का है और जो छिपा था उसे स्पष्ट कर दिया गया था। वहां हम स्पष्टीकरण 2 के प्रभाव पर विचार कर रहे थे।

(4) बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि यदि निर्धारिती इसकी शुद्धता को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए खुला है। लेकिन साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी हैं, और विभाग को बोर्ड के निर्णय के विरोध में तर्क देने की ४नुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में, हमें ऊपर उल्लिखित परिपत्र को प्रभावी करना होगा, क्योंकि यह निर्धारिती के पक्ष में है और विभाग को बाध्य करेगा।

(5) हमारे पहले के निर्णय और सर्कुलर बिंदु पर निर्धारिती के पक्ष में तीन उच्च न्यायालयों के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम निर्धारिती की ओर से संदर्भित निर्णयों से सहमत हैं और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से ४सहमति रखते हैं। , और यह मानते हैं कि केवल

साझेदारों द्वारा फर्म को भुगतान किए गए ब्याज को समायोजित करने के बाद फर्म द्वारा खूने साझेदारों को भुगतान की गई शुद्ध राशि को खूधिनियम की धारा 40 (बी) के तहत खूस्वीकार किया जा सकता है। चूँकि इस मामले में साझेदारों ने फर्म को खूधिक ब्याज का भुगतान किया था, फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया ब्याज न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से खूस्वीकार नहीं किया गया था और न्यायाधिकरण ने खूतिरिक्त राशि को हटाने में सही था और हम निर्धारिती के पक्ष में संदर्भित प्रश्न का उत्तर देते हैं। , सकारात्मक में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

एस.सी.के.

खूस्वीकरण : स्थानीय भाषा में खूनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह खूपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी खून्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का खूग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा